फसल बीमा योजना

किसानों की लुटाई, रिलायंस की कमाई, मोदी ने करवाई

किसानों से वसूली पक्की पर मुआवजे का कानून नहीं

नरेन्द्र मोदी ने शायद तय कर लिया है कि 2019 में उनका लूट का पट्टा खत्म होने से पहले पूरा नहीं तो आधा देश तो अम्बानी, अडाणी को गिरवी रख ही जायेंगे। इसी कड़ी में उनका ताज़ातरीन प्रयास है-किसान फ़सल बीमा योजना। वैसे तो यह योजना कांग्रेस के टाईम में भी लागू थी लेकिन उसमें किसानों को डण्डे मार कर उनसे पैसा अम्बानी को दिलवाने का कोई प्रावधान न था। इसलिये यह योजना ज्यादा प्रचारित नहीं हुई। क्योंकि जब अम्बानी को कोई फ़ायदा नहीं तो उसका अपना भांड मीडिया इसका प्रचार भी क्यों करता। लेकिन अब मोदी जी की नज़र इस सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी पर पड़ चुकी है और वे इसका पूरा उपयोग कर रहे हैं, अपने भामाशाह अम्बानी के खजाने भरने के लिये।

कहने को किसान फ़सल बीमा योजना ऐच्छिक है और यह किसानों के लिये इतनी लाभदायी है कि अब तक करोड़ों किसान इसके सदस्य/उपभोक्त बन चुके हैं। लेकिन 56 इंच की छाती के दावों की पोल पिछले हफ़्ते झज्जर में इस योजना के विरोध में हुये 'एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट आफ़ीसरों' (ए.डी.ओ.) का काम सरकारी योजनाओं को लागू करना है लेकिन जब तक उन्हें इस योजना के किसान विरोधी पहलूओं का पता चला तो उन्होंने इसके विरोध में राज्यस्तरीय विरोध प्रदर्शन झज्जर में किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। किसी भी फ़सल का बीमा इस योजना में किसान करवा सकता है जिसमें बीमा के प्रीमियम का एक छोटा हिस्सा किसान भरता है और बड़ा हिस्सा सरकार। कहने को तो यह प्रावधान किसान हितैषी है और भांड सरकार इसका टोल भी खूब पीट रही है लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रीमियम किसानों की जेब से जाये या सरकार की-जाता तो जनता का ही पैसा है। और वापस कुछ आना नहीं है। क्योंकि इस योजना के बीमे का ठेका चार बीमा कम्पनियों के पास है और ये चारों ही प्राइवेट हैं क्योंकि सरकारी बीमा कम्पनी को तो इस योजना में फटकने भी नहीं दिया गया। और ठीक भी है उन 'कंगलों' के पास मोदी को देने को कोई ब्लैकमनी तो है नहीं तो फ़िर काहे की हिस्सेदारी। यह भी लूट की पहली सुनिश्चितता कि सरकारी कम्पनी को काम न दो ताकि प्राइवेट वाले से अपनी हिस्सापत्ति कभी भी वसूल लें। इसी कड़ी में दूसरे कदम सरकार ने ये उठाये कि किसानों से जबरदस्ती बीमा करवाना और नुक्सान होने पर बीमे का कोई भुगतान का पक्का कानून न बनाना।

पता चला है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले लाखों किसानों से बैंक मैनेजरों ने जबरदस्ती किस्त काटकर (बिना उनकी अनुमति के) उनका फ़सल बीमा कर दिया। इसी तरह से किसी भी तरह का किसी भी बैंक से ऋण लेने वाले किसानों से बीमा करवाया गया। हालांकि बिना सहमति के किसी भी तरह का ऐसे पैसा काटना गैरकानूनी है और बहुत सारे बैंक मैनेजर भयभीत भी है कि अगर इस बारे में किसानों ने मुकदमे कर दिये तो उनकी जेल हो जायेगी लेकिन अभी तो नौकरी बचानी ज्यादा जरूरी थी। पता चला है कि इस तरह से जबरदस्ती बीमा से हरियाणा सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपया किसानों से छीनकर रिलायन्स इन्श्योरेंस कंपनी को दे चुकी है। जिसके पास हरियाणा क्षेत्र है। और इसका लगभग आठ गुणा यानि 10-000 करोड़ रुपये सरकार प्रीमियम के अपने हिस्से के रूप में बीमा कम्पनी को दे चुकी है। यानि बैठे बिठाये रिलायन्स की जेब में 1100 करोड़ रुपये और चवन्नी का भी किसी को कोई भुगतान करना नहीं क्योंकि उसके कोई सुनिश्चित नियम है नहीं। कल तक दिल्ली में जेएनयू में गरीब छात्रों को मिलने वाली साल भर की कोई 300 करोड़ रुपये की सब्सिडी पर बवाल काटने वाले भाजपाई सूरमा क्या इस पर भी कुछ मुंह खोलेंगे।

किसानों की परेशानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब बीमा कंपनी का सर्वेयर जांच करने गांव पहुंचा तो पता चला कि खेत में तो धान बोया हुआ है जबकि बैंक मैनेजर ने तो फ़ार्म में बाजरा लिखा हुआ है। इस बात के, सवर्येर हज़ार-हज़ार रुपये प्रति एकड़ किसानों से अलग से रिश्वत ले रहे हैं जो किसान देने को मजबूर हैं। पता चला है कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान जैसी ज़्यादा पानी लेने वाली फ़सल बोने की मनाही है। लेकिन किसान ने तो धानबो ली। उधर जबरदस्ती बीमा करने वाला बैंक मैनेजर इस मनाही के कारण धान की फ़सल का तो बीमा कर नहीं सकता लिहाज़ा किसान को धोखे में रखकर बाजरा बोया हुआ दिखाकर उसका बीमा कर देता है जिसका खामियाज़ा किसान को भुगतना पड़ता है।

दूसरी धोखाधड़ी किसान के साथ एडीओ से करवाई जा रही है। हर बीमे पर उनसे रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि इस क्षेत्र में प्रति एकड़ लगभग इतनी उपज है। अब अगर किसान की पैदावार उस निश्चित की गई उपज से कम होती है तो उसकी फ़सल खराब हुई मानी जायेगी और वह बीमे का हकदार होगा नहीं तो नहीं। लेकिन वह निश्चित उपज एडीओ से इतनी कम लिखवाई जा रही है कि उससे कम पैदावार किसान की कभी होगी नहीं और उसे मुआवजा कभी मिलेगा नहीं। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वह तो बस बीमे का प्रीमियम अदा करने के लिये है। इसको एक उदाहरण से समझ लें। मान लें कि एक किसान धान बोता है जिसकी पैदावार लगभग 80 90 मण प्रति एकड़ है। हरित क्रान्ति से पहले यह पैदावार प्रति एकड़ औसत लगभग 15-20 मण प्रति एकड़ थी। सरकार एडीओ को अपनी रिपोर्ट में 15-20 मण प्रति एकड़ की रिपोर्टी देने को मजबूर कर रही है। जबकि जाहिर है कि किसान की फ़सल कितनी ही खराब हो जाय तो भी 15-20 मण। एकड़ तो हो ही जाती है। तो जाहिर है कि उसको बीमे का भुगतान नहीं होगा। जबकि इतनी कम उपज में उसकी लागत भी पूरी नहीं होती। एडीओ इसी झूठी रिपोर्ट के दबाव के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। उधर सरकार ने एडीओ के खिलाफ़ ऐस्मा लगाने की धमकी दी है जो दिखाता है कि सरकार किसके हित में काम कर रही है।

इधर उत्तर प्रदेश से खबर है कि इसी तर्ज पर सरकार वहां जबरदस्ती गन्ने की फ़सल का कंपलसरी बीमा लागू करने जा रही है। किसानों को इस तरह से लूटकर इस योजना को अपनी उपलब्धि बताने वालों को यह समझ लेना चाहिये कि अगले चुनाव में किसान उनको इतने लीतरे मारेंगे कि 56 इन्च की छाती सिकुड़कर छ: इन्च की ही रह जायेगी-एडीओ की रिपोर्ट की तरह।

अजातशत्रु

एनआईटी में जुआ-सट्टा पुलिस की कमाई का धंधा

फ़रीदाबाद (म.मो.) थाना एनआईटी प्रभारी मित्र पालकी नियुक्ति के बाद क्षेत्र की जनता तो बेहाल है लेकिन धंधेबाज़ खुशहाल है। जिसके चलते थाना क्षेत्र में क्राइम ग्राफ़ चरम सीमा पर है दिन दहाड़े चोरी, लूट-पाट, शराब तस्करी, जुआ सट्टा जम कर हर गली-मुहल्लों में चल रहा है। दर्जनों शराब तस्कर अवैध शराब बेचकर पुलिस कमिशनर के आदेशों की हवा निकालते नज़र आ रहे हैं, जुआरी, सट्टेबाज अपने धंधे खुलेआम कर एनआईटी पुलिस के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। अपराधी नंगे नाच रहे हैं। वहीं जनता सिर्फ़ अच्छे दिन खत्म होने का इंतज़ार कर रही है। वहीं शहर के विधायक मंत्री ओछी राजनीति कर टाईम पास कर रहे हैं।

थाना एनआईटी क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली गांधी कॉलोनी, फतेहपुर चंदीला, भगत सिंह कॉलोनी, एन एच 5 का सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एन ब्लॉक, एम ब्लॉक, के ब्लॉक, जे ब्लॉक, में दर्जनों धंधेबाज़ अपने गोरखधंधों को अंजाम दे रहे हैं। इन बलॉकों में धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रही है। मैच दाना की बुक लगाई जा रही है। ये काम कोई चोरी-छिपे नहीं बल्कि दिन-दहाड़े थाना एनआईटी पुलिस की शह पर हो रहा है। थाना एनआईटी पुलिस को बड़ी आसानी से इन अड्डों से अपना हिस्सा लेते देखा जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार थाना एनआईटी का स्टाफ़ हर महीने डेढ से दो लाख रुपये इन धंधेबाजों से वसूल कर रहा है। जिसके चलते इन धंधेबाज़ों के हौंसले बुलंद है।

वहीं एनआईटी क्षेत्र की जनता का कहना है कि थाना प्रभारी मित्रपाल की कार्यशैली को लेकर वो इतने बेहाल है कि उनका गली मुहल्लों में निकलना तक दुभर हो गया है। डीसीपी के दफ़्तर के ठीक सामने बने पार्क में सट्टेबाजों व जुआरियों का ताता लगा रहता है। रोज़ाना लाखों रुपये का जुआ सट्टा इस पार्क में खेला जाता है। वहीं इसी पार्क के पीछे बनी रोड पर एक पान सिगरेट का खोखा है। जिसका मालिक विकलांग है जिसका फ़ायदा उठाकर ये दुकानदार अपने यहां सुबह शाम जुआ सट्टा खिलवाकर मोटे रुपये कमा रहा है। इसके साथ ही सारे शहर के असामाजिक तत्वों का जमावड़ा खोखे में रहता है। वहीं एनएच ई के फुट गार्डन, एनएच, एल ब्लॉक राहुल कॉलोनी में जमकर देह व्यापार का धंधा चल रहा है।

पुराना सट्टेबाज़ पाले का भाई हरवंस जो शराब का धंधा भी जमकर करता है, ने सट्टे के लिये जब चकरी लगाई तो पुलिस ने उसके लिये अलग से 'हफ़्ता' मांगा। सोदेबाज़ी के बाद 15000 रुपये महीना तय हुआ। एक मंथली तो दे दी, उसके बाद हरवंस ने यह कह कर बदं कर दी कि काम नहीं आ रहा है। इस पर पुलिस ने कहा कि काम नहीं आ रहा तो चकरी बंद कर दे। लिहाज़ा 5 अक्टूबर से चकरी सट्टा बंद है।

चीनी पूंजी से करें प्यार और उत्पादों का करें बहिष्कार

फ़रीदाबाद (म.मो.) चीन द्वारा पाकिस्तान का कूटनीतिक समर्थन करने को लेकर भाजपाई राष्ट्रवादी आजकल चीन से आयातित उत्पादों के बहिष्कार का ड्रामा कर रहे हैं। दूसरी ओर गत माह हरियाणा के उद्योग मंत्री एवं स्थानीय विधायक विपुल गोयल इस बात को लेकर कई दिन तक अपनी पीठ थपथपाते रहे कि चीन की एक कम्पनी जियोनी यहां अपना कारखाना लगाने आ रही है जिसमें सस्ते मोबाइल हैंडसेट बना करेंगे। इस बात को लेकर तमाम संघी व उनके समर्थक कई दिनों तक विपुल गोयल, मुख्यमंत्री खट्टर व केन्द्र की मोदी सरकार को बधाइयां देते रहे।

व्यापार में कोई किसी पर अहसान नहीं करता। अहसानों एवं भावुकता से व्यापार नहीं चला करता। व्यापार चलता है शुद्ध मुनाफ़े के आधार पर। अकेले भारत से नहीं, पूरी दुनिया से चीन व्यापार करता है। इसी व्यापार के द्वारा उसने अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत एवं सुदृढ बनाया है। कोई भी देश अथवा वहां के निवासी केवल इस आधार पर माल को पसंद या रिजेक्ट नहीं करते हैं कि यह चीन का बना है या पाकिस्तान का। पसंद का आधार होता है गुणवत्ता एवं कीमत। चीन का माल कोई खरीदता है तो केवल इसलिये कि वह पसंद आता है, खरीददार को पड़ता खाता है। छोटी-मोटी उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़िये, स्टील जैसी आधारभूत आइटम चीन से बन कर आती है जो भारत में बने स्टील से सस्ती पड़ती है जबकि लौह अयस्क (कच्चा लोहा) भारत से चीन को जाता है, कुछ चोरी से कुछ मंजूरी से।

वर्षों से चल रहा भारत-चीन व्यापार का सन्तुलन सदा से ही चीन के पक्ष में रहा है। इस व्यापार सन्तुलन का अर्थ होता है कि चीन भारत को निर्यात अधिक करता है और आयात कम करता है। इसी से उसे विदेशी मुद्रा का भारी लाभ होता है। चीन या किसी भी देश के उत्पादों का बहिष्कार करने की बजाय यह सोचना-समझना जरूरी है कि वह देश सस्ता और बढिया माल बना कैसे रहा है? अपने आप को धोखा देने के लिये लोग समझ बैठते हैं कि वहां तो लेबर मुफ़्त के बराबर सस्ती है। लेकिन यह गलत है, भारत से सस्ती लेबर आज दुनिया में कहीं नहीं है।

चीन ने लगातार अनुसंधान द्वारा अपनी प्रोद्योगिकी एवं तकनीक को उन्नत किया है। प्रचुर मात्रा में शिक्षण एवं तकनीकी संस्थानों (स्कूल आईटीआई, पोलिटेक्निक व इन्जीनियरिंग कॉलेज आदि)स्थापित करके कुशल एवं दक्ष कामगारों की कमी को दूर किया है। इसके अलावा वहां भारत की तरह ना तो लालफ़ीताशाही है और न ही भ्रष्टाचार। जहां भारत में केरल की रबड़ और बिहार से कोयला ट्रकों में आता है, वहीं चीन में यह काम रेल गाड़ी से होता है जिसकी लागत एक चौथाई से भी कम आती है। यहां उद्योग के लिये प्लॉट व लाइसेंस आदि लेने के लिये विभिन्न सरकारी महकमों के चक्कर काटने पड़ते हैं, सीएलयू के लिये रिश्वत देनी पड़ती है। बिजली कनेक्शन के लिये मोटी रिश्वत और बदले में महंगी बिजली मिलती है। इसके बाद दर्जनों इन्स्पेक्टरों की मंथली अलग से। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। इसी से उत्पादन लागत में भारी अन्तर पड़ जाता है।

चीन के माल का बहिष्कार तो अपने आप हो जायेगा यदि भारत में उनसे बेहतर व सस्ता माल बनने लगे। इसलिये बजाये ड्रामेबाज़ी करने के अपनी उत्पादन नीति को ठीक करना चाहिये। यदि इसके बिना भी बहिष्कार करना है तो सरकार उनके आयात पर ही प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा देती? सारा झगड़ा ही खत्म हो जायेगा। लेकिन प्रतिबन्ध तो दूर यहां तो उनकी पूंजी निवेश को लेकर ही तमाम भाजपाई गदगद होकर नाचे-नाचे घूम रहे हैं। यहां फ़ैक्ट्री लगाने के बाद तो वह चीनी कम्पनी यहीं के संसाधनों का दोहन करेगी और यहीं माल बेच कर मुनाफ़ा अपने देश में भेजेगी।

यदि किसी को मुगालता हो कि चीन वाले यहां जो निवेश करने आ रहे हैं, भारतीयों की भलाई एवं उन्नति के लिये आ रहे हैं तो उन्हें यथा शीघ्र इसे दूर कर लेना चाहिये। वे आ रहे हैं केवल अपने आर्थिक हितों को साधने के लिये न कि स्थानीय लोग़ों के हितों के लिये।

इलाज के नाम पर लूट का कारोबार

-अजय गुप्ता

आगरा के एक डॉक्टर बहुत अनुभवी हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। उनकी फ़ीस 700 रुपये है। अगर कोई मरीज़ एक घण्टे बाद भी दुबारा दिखाने जाये तो उसे फ़िर से फ़ीस भरनी पड़ती है। उनके क्लीनिक पर नियमों का इतनी सख्ती से पालन होता है कि मरीज़ के मरने के बाद भी उसका मृत शरीर ले जाने की तब तक अनुमति नहीं, जब तक उसके परिजन पूरा हिसाब नहीं कर देते। यही हाल गोरखपुर के एक त्वचारोग विशेषज्ञ का है। पहले वे मेडिकल कॉलेज में काम करने के अलावा आवास पर फ़ीस ले कर सुबह-शाम 100 से ज्यादा मरीज़ देखते थे। अब सेवानिवृत होने के बाद अपने दो बच्चों के साथ इस परिवार ने पीएंडजी क्लिनिक खोल रखा है। तीनों मिलकर 250 से ज्यादा मरीज़ देखते हैं। तीनों डॉक्टर अपने-अपने मरीज़ से 400 रुपये फ़ीस के वसूलते हैं। इसके अलावा इनके यहां सर्जरी, लेजर थिरेपी और सिकाई की सुविधा उपलब्ध है। एक साधारण सर्जरी का वे 30 हज़ार से 50 हज़ार रुपये तक लेते हैं। क्लिनिक पर मेडिकल स्टोर भी है। मरीज़ वहीं से दवा लेने के लिये बाध्य होता है, क्योंकि इन डॉक्टरों की लिखी दवा किसी अन्य मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती। पूरे परिवार की एक दिन की कमाई 2 लाख से ऊपर है। गोरखपुर के एक अन्य डॉक्टर जो फ़ीस नहीं लेते बल्कि दवाइयों के दाम ही लेते हैं। वे दवाइयों की पुड़िया बनाकर देते हैं और पर्चे पर दवाइयों के नाम इतना घसीट कर लिखते हैं कि उनके क्लिनिक के स्टाफ़ के अलावा कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता।

कई डॉक्टर एक दिन में जितना कमाते हैं, उतना एक सामान्य मज़दूर जिंदगी भर हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा सकता। प्राइवेट क्लिनिक या अस्पताल में आने वालों से बात करें तो अधिकांश मरीज़ यह शिकायत करते हैं कि तीन-चार साल इलाज कराने के बाद भी बिमारी जड़ से खत्म नहीं हुई। निराश होकर जब वे दूसरे

शेष पेज सात पर